

भारत@100 (संशोधित)

हरेंद्र बेहेरा, वी. धन्या, कुणाल प्रियदर्शी और सपना गोयल[^] द्वारा

यह लेख 2047-48 तक भारत को एक विकसित देश बनने में सक्षम बनाने के लिए एक सांकेतिक रोडमैप प्रदान करता है, जिसके लिए अगले 25 वर्षों में भारत की वास्तविक जीडीपी को 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाना होगा, जिससे इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्तमान के 2,500 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 22,000 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। विकास के स्थायी मार्ग के लिए भौतिक पूंजी में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाले क्षेत्रों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और नागरिकों के बीच सहयोग आवश्यक है।

परिचय

15 अगस्त, 2022 को - भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए अगले 25 वर्षों के लिए एक दृष्टिकोण रखा। सबसे बड़े लोकतंत्र, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, युवा देश के रूप में और गतिशील जनसंख्या, विशाल मध्यम वर्ग और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, भारत इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए तैयार है। इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए, मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, संरचनात्मक सुधारों, जनसांख्यिकीय लाभांश, जनशक्ति कौशल, तकनीकी प्रगति, धारणीय प्रथाओं और सुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई प्रमुख कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2047 तक एक विकसित देश बनने के लिए भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को मौजूदा स्तर¹ से बढ़ाकर इसे 8.8 गुना करना होगा। यह काफी हद तक नीतिगत बदलावों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। यह लेख अगले 25 वर्षों में विकास

[^] लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। लेखक लेख पर उनके इनपुट और उपयोगी सुझावों के लिए जी.वी. नथनएल, धीरेंद्र गजभिए, मोनिका सेठी, सिद्धार्थ नाथ, अभिनंदन बोराड, शोभित गोयल, राजस सरौए, सक्षम सूद, सिलु मुदुलि और अर्पिता अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

के संभावित चालकों और उन चुनौतियों का पता लगाता है जो प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समय पर और लक्षित नीति प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता पैदा कर सकती हैं।

अगला भाग एक विकसित देश को परिभाषित करने के मानदंड प्रस्तुत करता है और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारत के लिए आवश्यक विकास दर का अनुमान लगाता है। खंड III अंतर देशीय अनुभवों का संदर्भ देकर भारत के एक विकसित देश बनने की व्यवहार्यता का पता लगाता है। खंड IV भारत में विकास के संरचनात्मक चालकों और चुनौतियों की जांच करता है। खंड V लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोडमैप प्रदान करता है, इसके बाद खंड VI में निष्कर्ष दिया गया है।

II. भारत एक विकसित देश के रूप में

किसी देश को 'विकसित' के रूप में परिभाषित करने के लिए किसी अद्वितीय मानदंड का उपयोग नहीं किया जाता है। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) के आधार पर देशों को निम्न-आय, निम्न-मध्यम-आय, उच्च-मध्यम-आय और उच्च-आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत करता है। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार, 2022-23 में 13,205 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश को उच्च आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) देशों को तीन मानदंडों: (i) प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी); (ii) निर्यात विविधीकरण; और (iii) वैश्विक वित्तीय एकीकरण के आधार पर दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करता है: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (ईई) और उभरती बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)। चूंकि पीसीआई एकमात्र सामान्य मानदंड है और आईएमएफ द्वारा उन्नत देश श्रेणी के लिए कोई पीसीआई सीमा नहीं दी गई है, 2022 में ईई के बीच दर्ज की गई सबसे कम पीसीआई (क्रोएशिया के लिए 18,427 अमेरिकी डॉलर) को इस लेख में एक 'उन्नत' अर्थव्यवस्था के रूप में किसी देश का मूल्यांकन करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में माना गया है।

लक्ष्य

विकसित देश के उपरोक्त दो वर्गीकरणों के आधार पर, 2047-48 तक 2 प्रतिशत की वार्षिक औसत वैश्विक

¹ इस पूरे लेख में वित्तीय वर्ष वर्ष 2047 का प्रयोग 2047-48 के लिए किया गया है।

सारणी 1: 2047-48 में भारत के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी का लक्ष्य स्तर (अंतर्निहित वार्षिक औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि)

	मौजूदा	पूर्वानुमानित	उन्नत अर्थव्यवस्था (आईएमएफ वर्गीकरण)	उच्च आय वाले देश (विश्व बैंक वर्गीकरण)
	2021-22	2022-23	2047-48	2047-48
सांकेतिक जीडीपी (यूएसडी बिलियन)	3.150	3.388	49,069	35,025
सांकेतिक प्रति व्यक्ति जीडीपी (यूएसडी)	2,302	2,450	30,351	21,664
आवश्यक सांकेतिक जीडीपी (यूएसडी बिलियन) सीएजीआर (%)			11.3	9.8
आवश्यक सांकेतिक प्रति व्यक्ति जीडीपी (यूएसडी) सीएजीआर (%)			10.6	9.1
आवश्यक वास्तविक जीडीपी (आईएनआर) सीएजीआर (%)			9.1	7.6

स्रोत: आईएमएफ; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); विश्व बैंक; लेखकों की गणना।

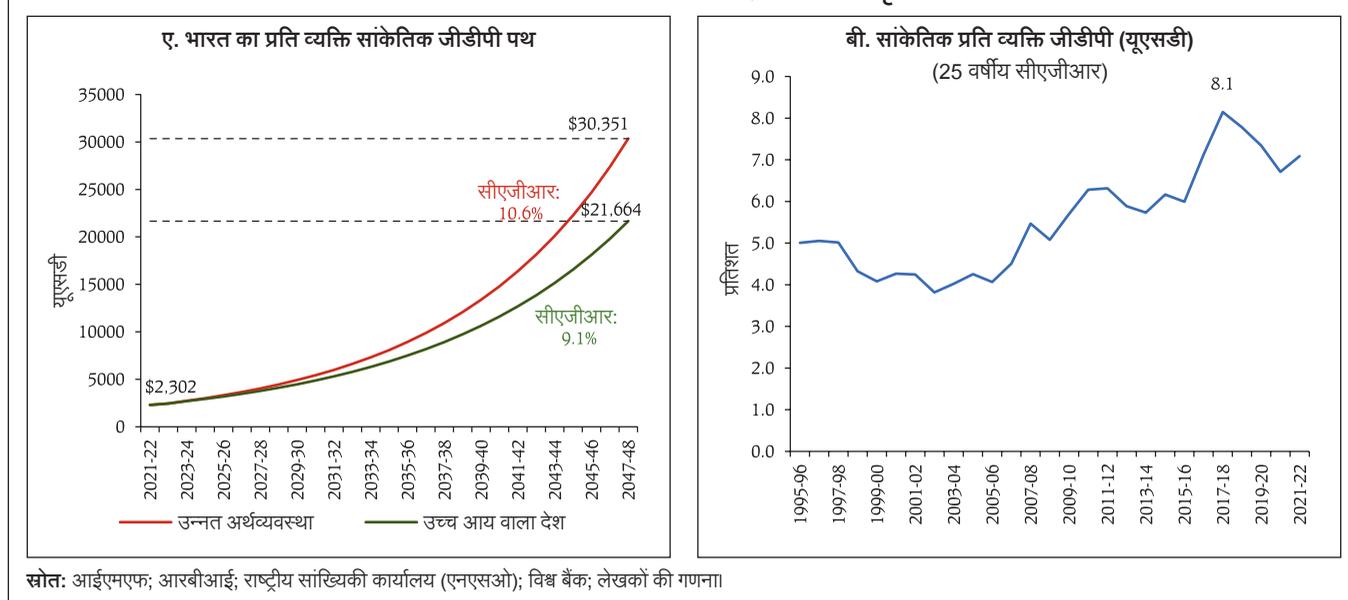
मुद्रास्फीति मानकर दो परिदृश्यों पर विचार किया गया है (सारणी 1)²:

1. **ई का आईएमएफ वर्गीकरण:** 2047 तक **ई** का दर्जा हासिल करने के लिए, देश की प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी 30,351 अमेरिकी डॉलर से अधिक होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2023-24 से 2047-48 के दौरान भारत के लिए आवश्यक वास्तविक जीडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 9.1 प्रतिशत होनी चाहिए।

2. **उच्च आय वाले देश का विश्व बैंक वर्गीकरण:** 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए किसी देश की प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी 21,664 अमेरिकी डॉलर से अधिक होनी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत के लिए आवश्यक वास्तविक जीडीपी सीएजीआर काम करता है। 2023-24 से 2047-48 के दौरान 7.6 प्रतिशत होगी।

2047-48 तक **ई** (उच्च आय वाला देश) बनने के लिए, नाममात्र के संदर्भ में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को 10.6

चार्ट 1: लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक वृद्धि दर



² **ई** की तुलना में भारत की मुद्रास्फीति का अंतर 2047-48 तक 2 प्रतिशत माना गया है; तदनुसार, भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है (भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य के 4 प्रतिशत में से शेष 2 प्रतिशत को उत्पादकता अंतर द्वारा समझाया गया है)। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की गणना के अनुमान के अनुसार जनसंख्या वृद्धि औसतन 0.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

प्रतिशत (9.1 प्रतिशत) का सीएजीआर रिकॉर्ड करना होगा (चार्ट 1)³। हालाँकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1993-94 से 2017-18⁴ के दौरान अतीत में लगातार 25 वर्षों की अवधि में भारत ने जो सर्वश्रेष्ठ हासिल किया है, वह 8.1 प्रतिशत का सीएजीआर है।

III. लक्ष्य प्राप्त करने की व्यवहार्यता: अंतर देशीय अनुभव

लंबे समय तक उच्च विकास हासिल करना आर्थिक इतिहास में दुर्लभ बात नहीं है; निरंतर उच्च विकास चरणों के प्रकरण हाल ही के हैं और उच्च विकास को बनाए रखने में प्रौद्योगिकी और वैश्वीकृत बाजारों के महत्व को उजागर करते हैं। यह कहा जा सकता है कि भारत को 9.1 प्रतिशत की नाममात्र प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने पिछले रिकॉर्ड को पार करना होगा। लगातार 25 वर्षों की अवधि में अपने-अपने उच्च विकास चरणों के दौरान इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहे हमारे पड़ोसी देशों का विकास रिकॉर्ड बताता है कि इनमें से अधिकांश देशों ने निम्न आय स्तर से शुरुआत की थी। दक्षिण कोरिया द्वारा 1966-1990 के दौरान 17.9 प्रतिशत का उच्चतम सीएजीआर दर्ज किया गया था, जो 1965 में 109 अमेरिकी डॉलर के निम्न प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से शुरू होकर 1990 में 6,610 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। चीन, हालांकि अभी तक एई या उच्च आय वाला देश नहीं है 1983-2007 के दौरान 10.9 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई, जो 1982 में 203 अमेरिकी डॉलर के स्तर से बढ़कर 2007 तक 2,694 अमेरिकी डॉलर हो गई। इस प्रकार, अन्य देशों द्वारा अपने संबंधित उड़ान के चरणों के दौरान अनुभव किए गए विकास प्रक्षेपवक्र से पता चलता है कि भारत की संभावनाएं बढ़ रही हैं। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र संभव है।

उच्च आय की स्थिति की ओर संक्रमण को चिह्नित करती हैं, वे हैं औद्योगीकरण का सचेत निर्णय और बाहरी व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन ने अपने विकास को गति देने के लिए उद्योग - विशेषकर विनिर्माण - पर

विशेष जोर दिया। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र के लिए विकास की आवश्यकता को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और कम लागत और प्रशिक्षित श्रम बल द्वारा पूरा किया गया।

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के सचेत निर्णय का परिणाम निर्यात अभिविन्यास था जिसने बाजार प्रदान किया और संस्थाओं की दक्षता में सुधार करने में मदद की। उनके लक्षित उपायों में शामिल हैं: (i) विनिर्माण-दर मूल्यहास; (ii) प्राथमिकता प्राप्त ऋण आवंटन, कर छूट और निर्यात प्रोत्साहन के पक्ष में अन्य प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन; (iii) श्रम-गहन विनिर्माण में तुलनात्मक लाभ का उपयोग करना और बाद में, पूंजी-गहन या कौशल-गहन उत्पादों को बढ़ाना; और (iv) निर्यात क्षमता वाले नए उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियां। इसके अलावा, 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत के दौरान विश्व आय में तेजी से वृद्धि से उन्हें मदद मिली जिससे निर्यात की मांग में वृद्धि हुई।

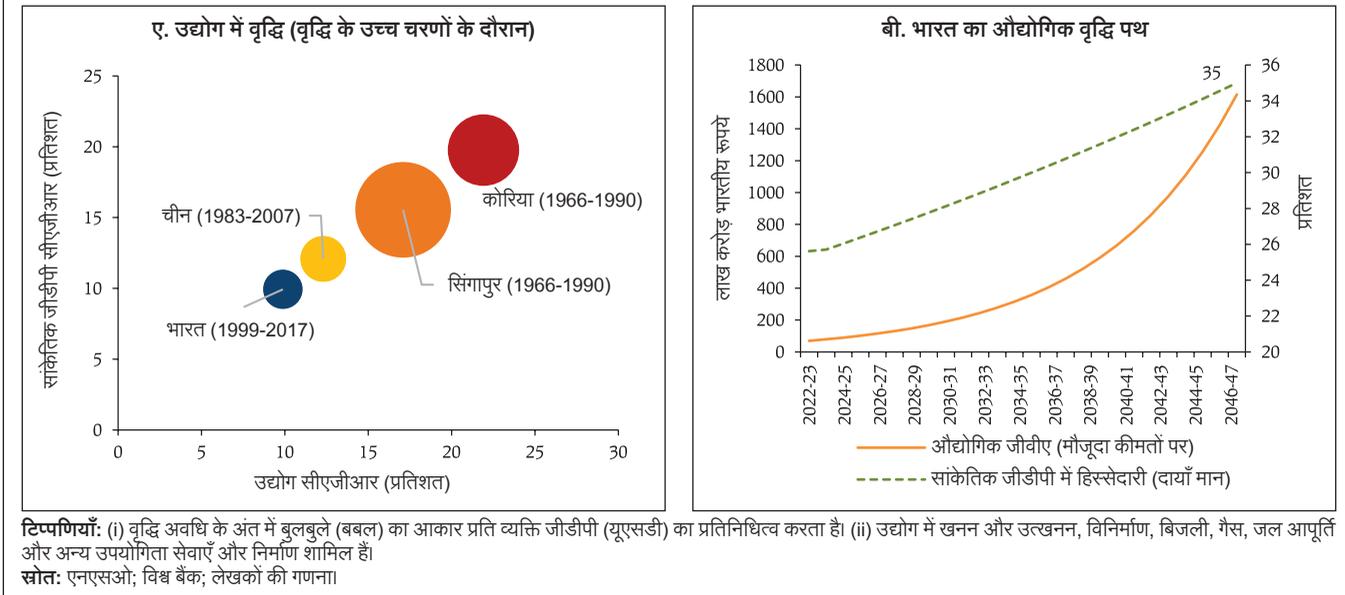
इन देशों की तुलना में, जहां कृषि से उद्योग और सेवा क्षेत्र तक संरचनात्मक परिवर्तन हुए, भारत ने सेवा क्षेत्र में छलांग लगा दी, जबकि औद्योगिक क्षेत्र स्थिर रहा। अगले 25 वर्षों में विकास को बनाए रखने के लिए, भारत को अपने औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करके अपनी आर्थिक संरचना को पुनर्संतुलित करना होगा, जिसका पीछे और आगे का मजबूत संबंध है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा, एक व्यापक औद्योगिक क्षेत्र का मतलब यह होगा कि भारत घरेलू स्तर पर बढ़ती आबादी की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम होगा। तदनुसार, यह उम्मीद की जाती है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र को 2047-48 तक अपनी हिस्सेदारी मौजूदा 25.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करनी चाहिए, जिसमें कुल मूल्य वर्धित मूल्य में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत होगी। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र को 13.4 प्रतिशत की मामूली सीएजीआर (चार्ट 2) पर बढ़ने की आवश्यकता होगी।

जबकि इन अर्थव्यवस्थाओं ने मुख्य रूप से विनिर्माण निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया है, वर्तमान परिदृश्य में सेवा निर्यात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सेवा निर्यात में भारत के तुलनात्मक लाभ को देखते हुए, यदि यह अगले 25 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात (नाममात्र) में 13.3

³ इसके बाद, सभी विश्लेषण विश्व बैंक वर्गीकरण पर आधारित हैं और 'विकसित' का प्रयोग 'उच्च आय' के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है।

⁴ यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अवधि उच्च मुद्रास्फीति से भी चिह्नित थी।

चार्ट 2: वृद्धि चालक: उद्योग

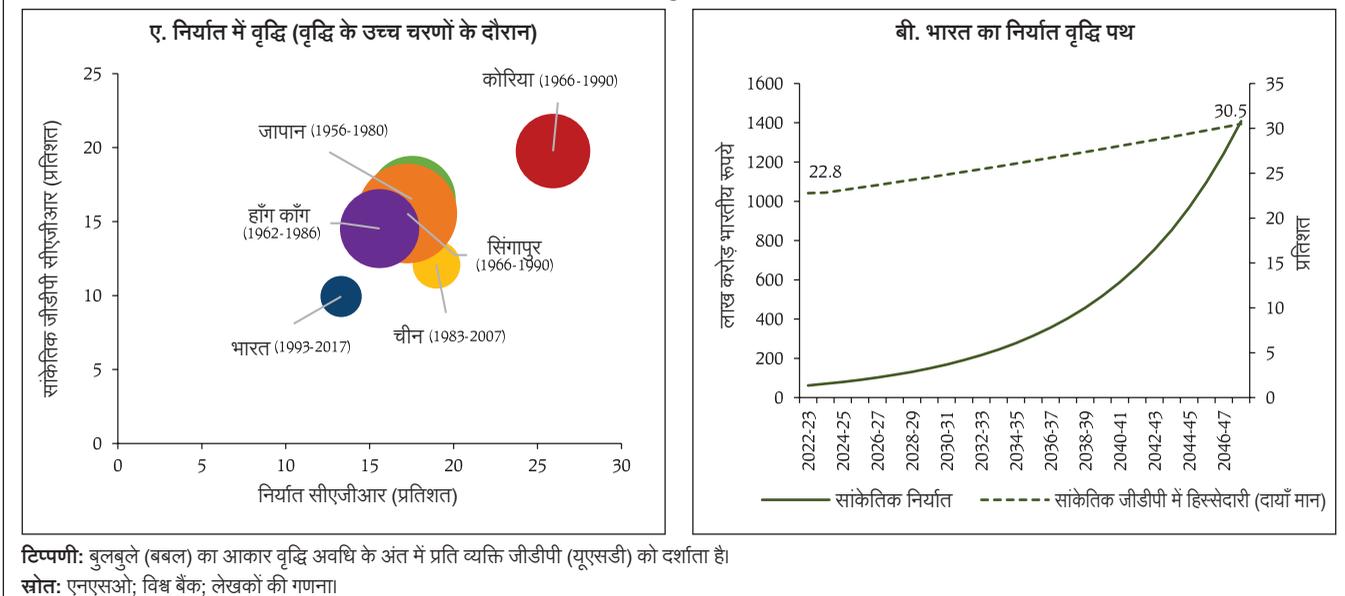


प्रतिशत की वृद्धि को बनाए रखने में कामयाब होता है (जैसा कि 1993-2017 के उच्च विकास चरण के दौरान देखा गया था), तो जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी 2022-23 में 22.8 प्रतिशत से बढ़कर 2047-48 तक 30.5 प्रतिशत हो जाएगी (चार्ट 3)।

एक अन्य विशेषता जिसने इन अर्थव्यवस्थाओं के विकास पथ को चिह्नित किया, वह कृषि के नेतृत्व से उद्योग और सेवाओं के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में क्रमिक संक्रमण था, जिसमें कृषि

क्षेत्र का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद (सारणी 2) के 5 प्रतिशत से नीचे आ गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय, कृषि का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक था, जो पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम हुआ है। आगे चलकर, कृषि की हिस्सेदारी को सेवाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ कम करना होगा जैसा कि ईई में देखा गया है। तदनुसार, 2047-48 तक क्षेत्रीय हिस्सेदारी क्रमशः 5 प्रतिशत और 60 प्रतिशत रखने के लिए आने वाले 25 वर्षों में

चार्ट 3: वृद्धि चालक: वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात



सारणी 2: सांकेतिक जीडीपी में हिस्सेदारी: 2022

देशों	उद्योग	सेवाएं	कृषि	निर्यात
दक्षिण कोरिया	31.8	58.2	1.6	48.3
चीन	39.9	52.8	7.3	20.7
जापान	28.8*	69.9*	1.0*	18.2*
सिंगापुर	24.2	70.9	0.0	186.6
हांगकांग	6.0*	89.7*	0.1*	193.9
औसत क्षेत्रीय मिश्रण	26.4	67.8	2.1	93.2
भारत	25.6	48.6	16.6	22.4

*: 2021 के लिए नवीनतम डेटा उपलब्ध हैं।

स्रोत: विश्व बैंक; लेखकों की गणना।

कृषि को 4.9 प्रतिशत की सीएजीआर और सेवा क्षेत्र को 13 प्रतिशत की दर से बढ़ना होगा।

इन विकास लक्ष्यों को साकार करने के लिए, भारत को संरचनात्मक परिवर्तन के साथ निरंतर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली विकास रणनीति की आवश्यकता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के साथ-साथ, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में विकास की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सर्वांगीण विकास को पूरा करना लक्ष्य होना चाहिए। अगले भाग में, हम विकास चालकों का विस्तार से पता लगाएंगे।

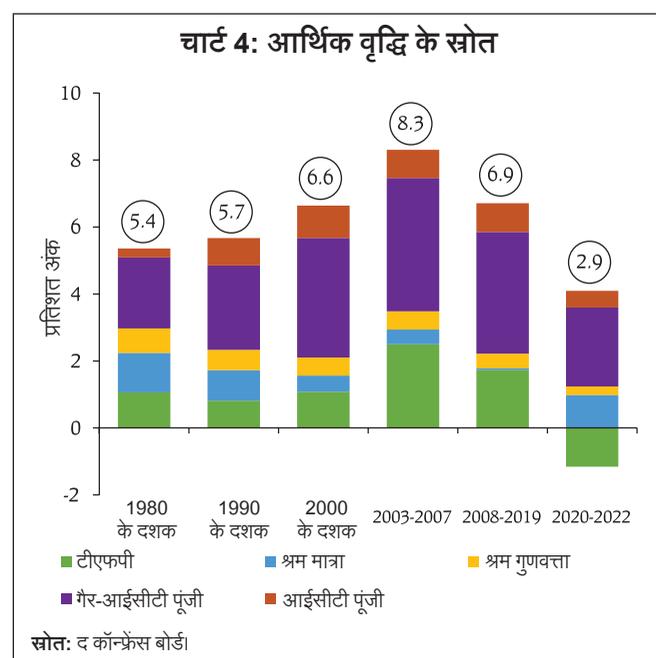
IV. विकास के वाहक**विकास का लेखांकन**

नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत यह मानता है कि आर्थिक विकास तीन कारकों का परिणाम है - श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी (सोलो, 1956; स्वान, 1956; सोलो, 1957)। रोजगार और निवेश में वृद्धि या तकनीकी उन्नति किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ा सकती है। बचत दर में वृद्धि या उच्च पूंजी प्रवाह किसी देश के पूंजी संचय में योगदान कर सकता है। इसी तरह, उत्पादन प्रक्रिया में अधिक लोगों को नियोजित करने (या उच्च श्रम बल भागीदारी दर) से समग्र उत्पादन में श्रम का योगदान बढ़ सकता है। हालांकि किसी देश के पास रोजगार पैदा करने या अधिक पूंजी जोड़ने के लिए सीमित संसाधन हो सकते हैं, लेकिन यह विकास के लिए प्रौद्योगिकी के योगदान को असीमित रूप से बढ़ा सकता है। इसलिए, मानव पूंजी और अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) में निवेश के माध्यम से प्रौद्योगिकी के नए रूपों और उत्पादन

के कुशल और प्रभावी साधनों - जिसे आम तौर पर कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) कहा जाता है - बनाकर विकास की लगातार उच्च दर हासिल की जा सकती है। (रोमर, 1986, 1990; अधिओन और हॉवित, 1992)।

विकास की गणना प्रक्रिया से पता चलता है कि भारत का विकास मुख्य रूप से गैर-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (गैर-आईसीटी) पूंजी द्वारा संचालित है। भारत एक श्रम-प्रचुर देश होने के बावजूद, समग्र विकास में श्रम की मात्रा और गुणवत्ता दोनों का योगदान कम है। टीएफपी ने 2003-07 के उच्च विकास चरण के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई, जीएफपी के बाद की अवधि में इसका योगदान कम हो गया और महामारी के दौरान ऋणात्मक हो गया (चार्ट 4)। कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पादकता में गिरावट का प्रभाव आंशिक रूप से 2021-2022 के दौरान मजबूत रोजगार वृद्धि के योगदान से कम हो गया है; हालांकि, मुख्य रूप से आईसीटी और गैर-आईसीटी पूंजी से अन्य खर्चों से कम योगदान के कारण समग्र वृद्धि प्रभावित हुई।

अगले 25 वर्षों में 7.6 प्रतिशत की वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि को बनाए रखने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए, 2023-47 की अवधि के लिए विकास लेखांकन ढांचे के भीतर पांच वैकल्पिक परिदृश्यों के साथ एक आधारभूत परिदृश्य तैयार



सारणी 3: दीर्घकालिक पूर्वानुमानों के लिए उत्पादन के कारकों में वृद्धि पर अनुमान

चर	आधारभूत (बेसलाइन)	वैकल्पिक_कौशल	वैकल्पिक_पूंजी	वैकल्पिक_आईसीटी	वैकल्पिक_कौशल_पूंजी_आईसीटी	2047 के लक्ष्य
श्रम के घंटे	रोजगार वृद्धि के समान	आधारभूत	आधारभूत	आधारभूत	आधारभूत	आधारभूत
श्रम गुणवत्ता (कौशल सेट)	5-वर्षीय चल औसत	बेसलाइन के साथ पहले वर्ष में 0.1 प्रतिशत अंक (पीपी) की क्रमिक वृद्धि, दूसरे वर्ष में 0.11 पीपी, तीसरे वर्ष में 0.12 पीपी, इत्यादि।	आधारभूत	आधारभूत	वैकल्पिक_कौशल	वैकल्पिक_कौशल
आईसीटी	5-वर्षीय चल औसत	आधारभूत	आधारभूत	2003-19 के दौरान देखी गई औसत वृद्धि	वैकल्पिक_आईसीटी	वैकल्पिक_आईसीटी माइनस 5 पीपी
गैर-आईसीटी	5-वर्षीय चल औसत	आधारभूत	2033 तक विकास में 0.2 पीपी की क्रमिक वृद्धि	आधारभूत	वैकल्पिक_पूंजी	वैकल्पिक_पूंजी माइनस 0.25 पीपी
टीएफपी	2003-16 के दौरान औसत वृद्धि देखी गई	आधारभूत	आधारभूत	आधारभूत	आधारभूत	बेसलाइन के साथ शुरुआती 5 वर्षों के लिए टीएफपी में 0.05 पीपी और उसके बाद 0.01 पीपी की क्रमिक वृद्धि।

पीपी: प्रतिशत अंक; एएलटी: वैकल्पिक; आईसीटी: सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

टिप्पणियाँ:

(ए) संयुक्त राष्ट्र की कामकाजी आयु की आबादी का उपयोग करके रोजगार संख्या उत्पन्न होती है और वर्ष 2022 में 40 प्रतिशत के स्तर से श्रम बल भागीदारी दर में प्रति वर्ष 1 प्रतिशत अंक (पीपी) की क्रमिक वृद्धि होती है।

(बी) नई शिक्षा नीति और सरकार द्वारा किए गए कई उपायों के प्रभाव को दर्शाते हुए, कौशल सेट को क्रमशः और धीरे-धीरे बढ़ने वाला माना जाता है।

(सी) आधारभूत परिदृश्य में टीएफपी के अपेक्षाकृत उच्च दर से बढ़ने का अनुमान है, जैसा कि 2003-16 के दौरान देखा गया, जो सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों को दर्शाता है।

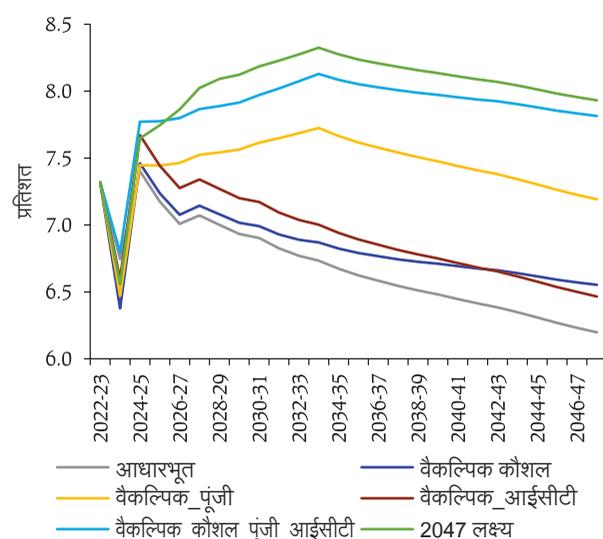
(डी) अतीत में बहुत मजबूत वृद्धि अनुभव की तुलना में गैर-आईसीटी पूंजी वृद्धि कम मानी जाती है; लेकिन वर्तमान वृद्धि दर से अधिक है। (ई) शेरर गुणांक 5-वर्षीय चल औसत स्तरों पर कल्पित हैं।

किया जा रहा है। इन परिदृश्यों में उत्पादन के सभी कारकों और समग्र उत्पादन में उनके संबंधित शेररों के संबंध में अलग-अलग धारणाएं शामिल हैं (सारणी 3)।

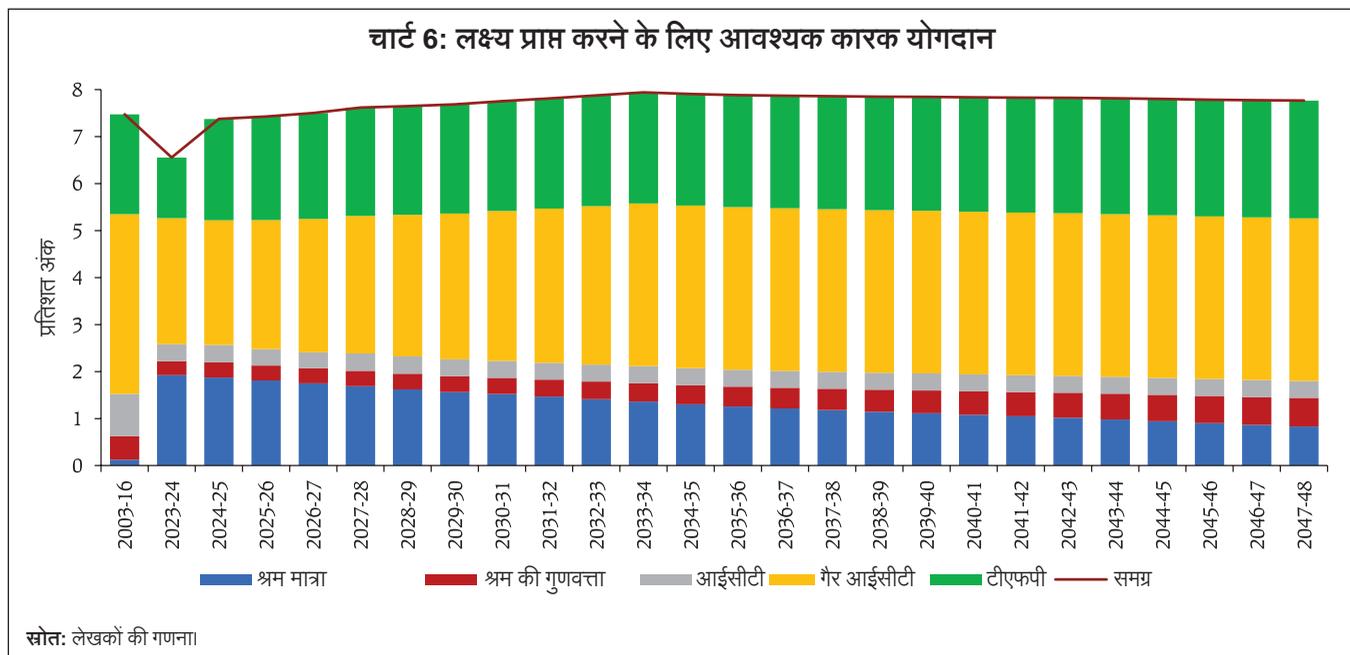
विभिन्न परिदृश्य विश्लेषण उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई के महत्व को रेखांकित करते हैं (चार्ट 5)। यथास्थिति जारी रखने से, जैसा कि आधारभूत परिदृश्य के तहत माना जाता है, अनुमानित वृद्धि विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्ष्य से काफी कम हो जाती है। यहां तक कि कौशल में वृद्धि या आईसीटी पूंजी में उच्च विकास दर मानने के बावजूद, जैसा कि 2003-19 के दौरान देखा गया था, भारत की वृद्धि अभी भी लक्ष्य से काफी नीचे गिर जाएगी। हालाँकि भौतिक पूंजी में उच्च वृद्धि से विकास की गति को कुछ बढ़ावा मिल सकता है, फिर भी यह वांछित वृद्धि (अल्ट_कैप परिदृश्य) से कम है। हालाँकि, श्रम गुणवत्ता और पूंजी में उच्च वृद्धि (अल्ट_स्किल_कैप_आईसीटी परिदृश्य) या श्रम गुणवत्ता, आईसीटी और गैर-आईसीटी पूंजी में

सुधार और अधिक उत्पादकता वृद्धि (2047 लक्ष्य परिदृश्य) का संयोजन, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अपनी यात्रा में सहायता करेगा।

चार्ट 5: वास्तविक जीडीपी वृद्धि पथ के परिदृश्य



स्रोत: लेखकों की गणना।



इसलिए, भौतिक पूंजी और टीएफपी से बड़े योगदान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है (चार्ट 6)। साथ ही, श्रम गुणवत्ता में सुधार एक निरंतर प्रयास होना चाहिए क्योंकि यह टीएफपी को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रति श्रमिक पूंजी बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे कार्यबल की उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि होगी। पूंजी निवेश और तकनीकी प्रगति के महत्व पर जोर देकर, भारत अपने श्रमिकों को अधिक कुशलता से उत्पादन करने के लिए सशक्त बना सकता है, जिससे लंबे समय में निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके।

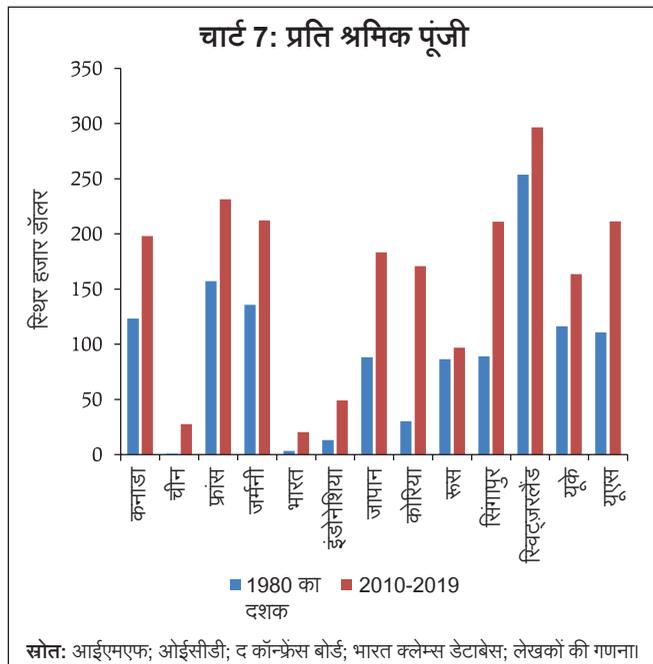
चुनौतियां

उन्नत उत्पादन के लिए पूंजी का संचय

2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह महत्वपूर्ण रूप से भौतिक और मानव पूंजी दोनों के विकास पर निर्भर करेगी। भारत में, निवेश को मुख्य रूप से घरेलू बचत और एक छोटा हिस्सा पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। कुल पूंजी निर्माण में निजी पूंजी की बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका के साथ उदारीकरण के बाद बचत और निवेश दरों में तेजी आई। हालाँकि, भारत की बचत दर 2007-08 में 37.8 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 2021-22 में 30.2 प्रतिशत हो गई है और

निवेश में भी मंदी देखी जा रही है। देश की विकास आवश्यकताओं को देखते हुए, पूंजी निर्माण के लिए घरेलू और बाहरी दोनों स्रोतों पर ध्यान देने के साथ पूंजी संचय को तेज गति से करने की आवश्यकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि भारत की घरेलू बचत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुख्य रूप से भौतिक संपत्ति, सोना और चांदी से बना है, इन संसाधनों को निवेश के लिए कुशलतापूर्वक जुटाने और निर्देशित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पूंजी प्रधान होती जा रही है, प्रति श्रमिक पूंजी और पूंजी-उत्पादन अनुपात में वृद्धि हाल की घटना है। फिर भी, भारत की प्रति कर्मचारी पूंजी एई और अन्य समकक्ष देशों की तुलना में कम है (चार्ट 7)। यह उत्पादकता को कम करके, नवाचार और तकनीकी प्रगति को बाधित करके आर्थिक विकास में बाधा डालता है। क्षेत्रीय स्तर पर, यह पाया गया है कि निर्माण और खनन क्षेत्रों में पूंजी की तीव्रता में वृद्धि पूंजी के असंगत उपयोग को उत्पादकता में बदलने में विफल रही (कृष्णा एवं अन्य., 2022)। इसलिए पूंजी निवेश के साथ-साथ उसकी उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान देना जरूरी है।



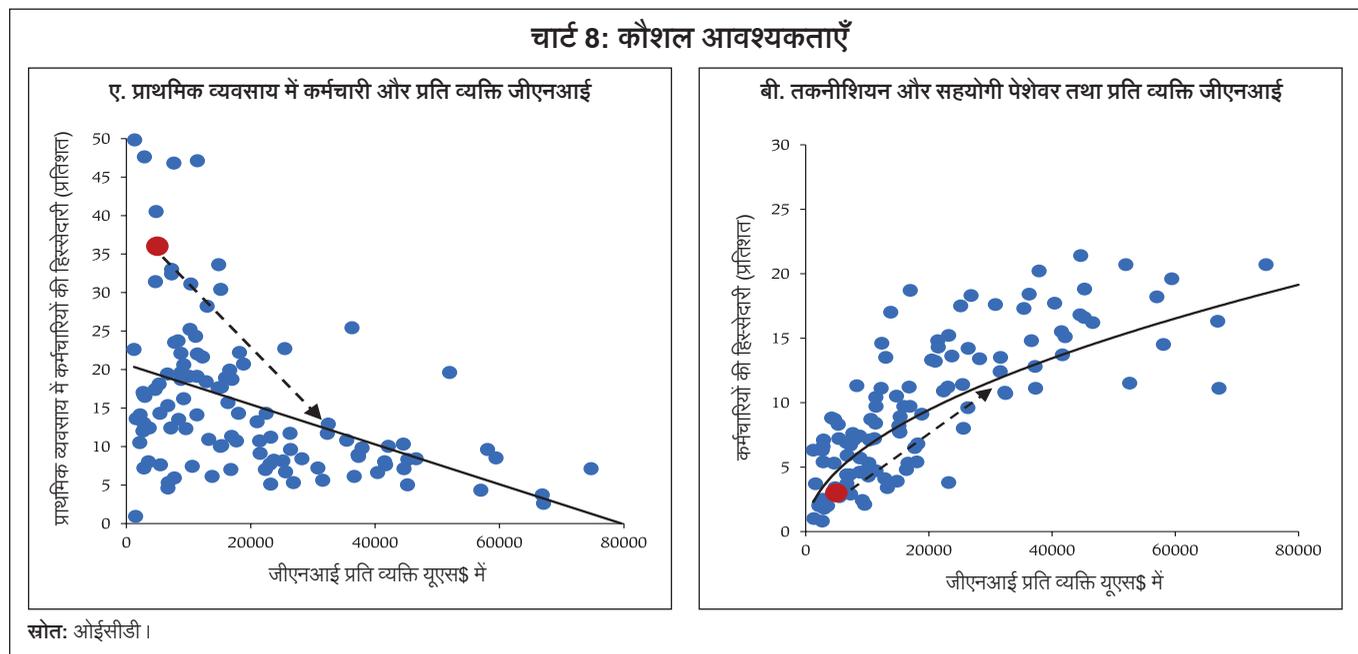
जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए भारतीय श्रम बल को कुशल बनाना

यह देखते हुए कि भारत के पास विशाल मानव संसाधन हैं, बड़ी कार्यशील आबादी का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी में

निवेश महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, भारत की 1.42 बिलियन की आबादी दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जिसकी औसत आयु 28.2 वर्ष है, और 68 प्रतिशत आबादी कामकाजी आयु वर्ग⁵ से संबंधित है। तेजी से बढ़ते तकनीकी विकास के संदर्भ में, श्रम बल का भविष्य का योगदान उनके लिए उपलब्ध कौशल-सेट पर निर्भर करेगा। भारतीय श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र (कुल रोजगार का 90 प्रतिशत से ऊपर)⁶ में कार्यरत है, और मौजूदा कार्यबल की रोजगार क्षमता⁷ केवल 50 प्रतिशत के आसपास है (पात्र, 2022)। अंतर देशीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के रोजगार में प्राथमिक व्यवसायों का वर्चस्व है और कौशल-आधारित व्यवसायों में पिछड़ा हुआ है (चार्ट 8)।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बढ़ावा देना

भारत को शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को प्राथमिकता देनी होगी; और निजी क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे देश बहुत कम हैं, जो अपनी श्रम शक्ति पर पर्याप्त मात्रा में निवेश किए बिना उच्च आर्थिक विकास की निरंतर अवधि हासिल किए हैं। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सामान्य सरकारी व्यय क्रमशः सकल



⁵ विश्व जनसंख्या संभावनाएँ 2022, संयुक्त राष्ट्र।

⁶ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

⁷ रोजगार योग्यता एक उत्पाद (कौशल) का एक सेट जो सक्षम बनाता है) और एक प्रक्रिया दोनों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को विपणन योग्य कौशल प्राप्त करने और उसे बेहतर बनाने के लिए सशक्त बनाता है जिससे लाभकारी रोजगार प्राप्त हो सकता है।

घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत और 3.1 प्रतिशत है, जो दोनों संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं (क्रमशः औसत 4.7 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत) और विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं) की तुलना में कम है (औसत क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत)।

कुल कारक उत्पादकता बढ़ाना

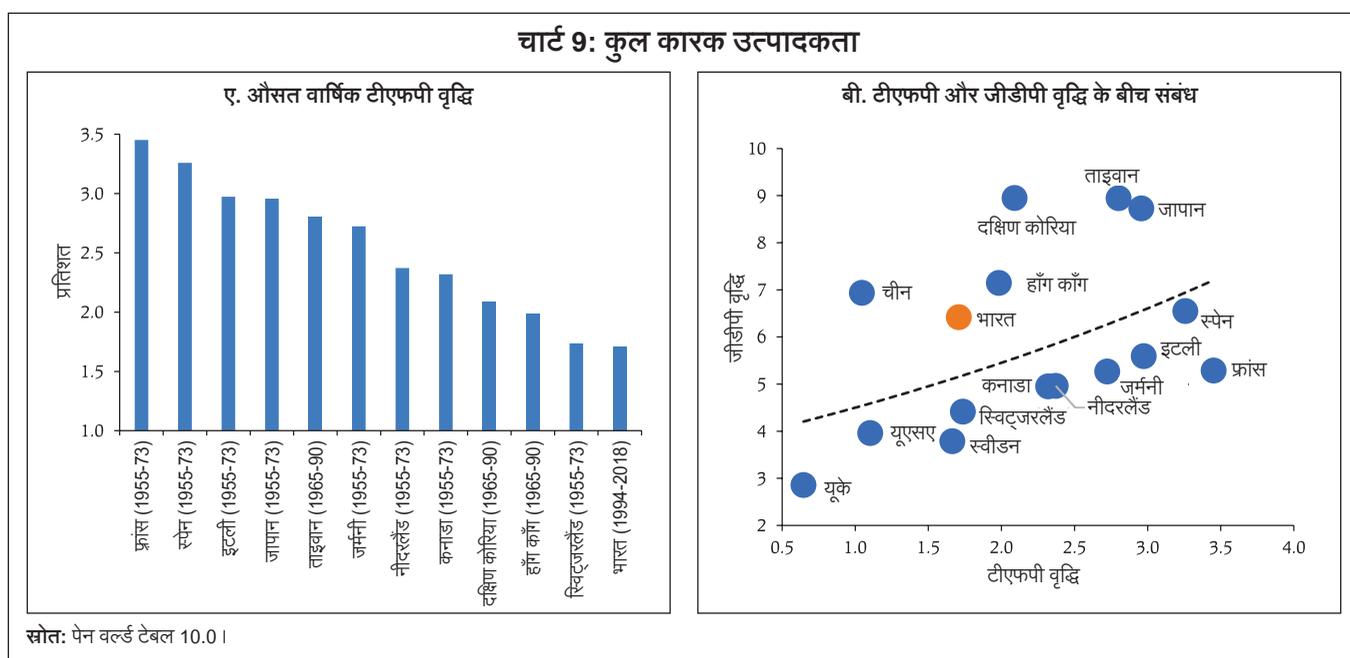
अंतर देशीय संदर्भ में अध्ययनों से पता चला है कि टीएफपी वृद्धि उनकी वृद्धि के एक प्रमुख हिस्से की व्याख्या करती है (आइचेंग्रीन एवं अन्य., 2012; बुलमैन एवं अन्य., 2014; किम एंड पार्क, 2017)। टीएफपी वृद्धि को किसी देश के मध्य-आय से उच्च-आय वाले देश समूह (किम और पार्क, 2017) में ऊपर की ओर संक्रमण में एक प्रमुख कारक माना जाता है; इसलिए, मध्यम आय वाले देशों को "इनपुट-संचालित से टीएफपी-संचालित विकास में संक्रमण" पूरा करना होगा (ट्रान, 2013) ।

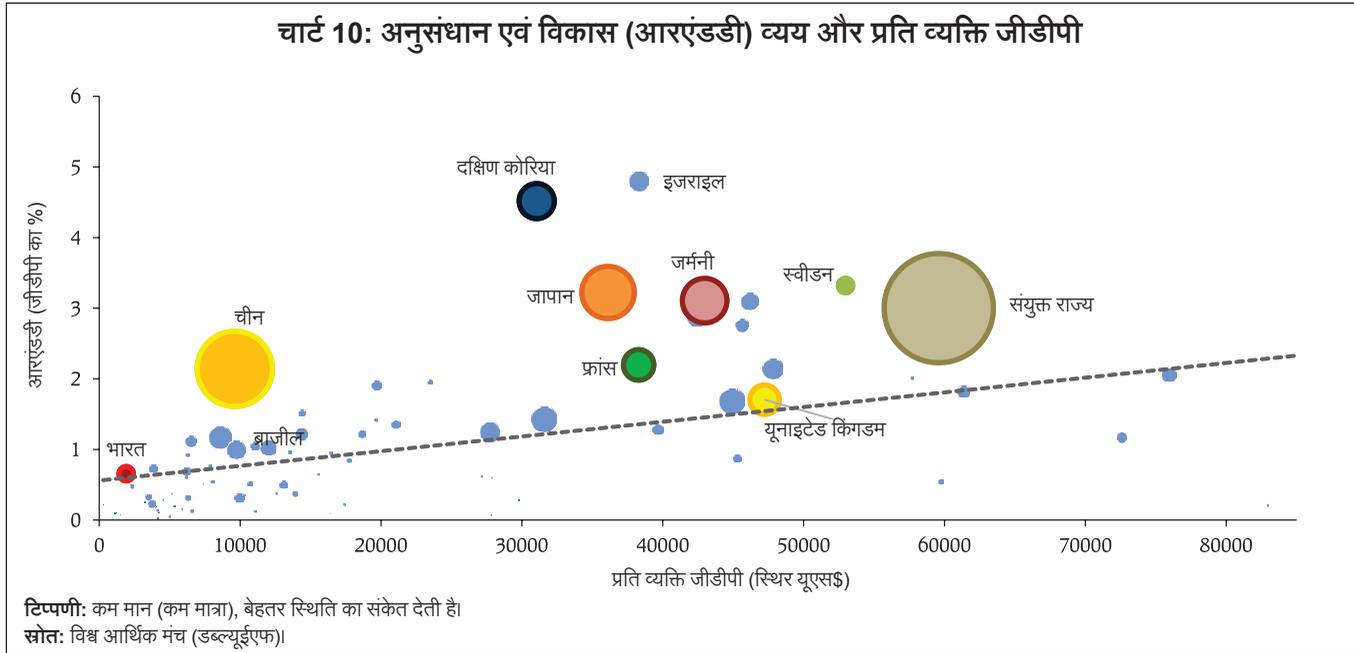
आज के अधिकांश उन्नत देशों ने अपने उच्च-विकास चरणों के दौरान भारत की तुलना में अधिक टीएफपी वृद्धि देखी है। उदाहरण के लिए, 1955 और 1973 के बीच अपने उच्च विकास चरणों के दो दशकों के दौरान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और जापान जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने प्रति वर्ष 2.7 से 3.5 प्रतिशत की सीमा में टीएफपी वृद्धि का अनुभव किया। इसके विपरीत, दुनिया की प्रमुख बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद

1994 - 2018 के दौरान भारत की टीएफपी वृद्धि प्रति वर्ष केवल 1.7 प्रतिशत थी (चार्ट 9)। उत्पादकता बढ़ाने के लिए, निम्न से उच्च-उत्पादक क्षेत्रों में श्रम बल के पुनः आवंटन के साथ-साथ मजबूत मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से घरेलू फर्मों तक वैश्विक सीमांत प्रौद्योगिकियों का तेजी से प्रसार आवश्यक है।

टीएफपी को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना और नवाचार को मजबूत करना

अनुसंधान एवं विकास में कम निवेश, विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा, संभावित उत्पादकता लाभ से लाभ प्राप्त करने में एक प्रमुख बाधा है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की अवधि में आर्थिक मंदी के बावजूद, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने अपने अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि की, जबकि भारत के लिए यह कम और लगभग अपरिवर्तित रहा (पिछले दो दशकों से सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत)। 2009 और 2018 के बीच दक्षिण कोरिया, जर्मनी और चीन का कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय उनके संबंधित सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत था (चार्ट 10) । वैश्विक स्तर पर दिए गए कुल पेटेंट में भारत में लागू और दिए गए पेटेंट की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में बढ़ रही है, भले ही यह 1 प्रतिशत से नीचे है। अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ाने के लिए निजी





क्षेत्र द्वारा अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी, सरकार प्रोत्साहन प्रदान करके, निजी क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करके, नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के प्रवर्तन को मजबूत करके एक सक्षम वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

V. लक्ष्य प्राप्त करने का रोडमैप

इतिहास संभावित विकास पथ प्रदान करता है, लेकिन निर्यात-आधारित विकास रणनीति जिसने अतीत में जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को मदद की थी, वर्तमान समय में भारत के लिए लागू या उपलब्ध नहीं हो सकती है, विशेष रूप से कमजोर मध्यम अवधि के वैश्विक विकास दृष्टिकोण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए। दूसरी ओर, वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र विनिर्माण से प्रेरित आर्थिक विकास के विपरीत विकास का पावरहाउस बन गया है। भारत को विकास के विभिन्न पहलुओं अर्थात् मजबूत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, कृषि से अन्य क्षेत्रों में श्रम के पुनः आवंटन को सक्षम करने वाले संरचनात्मक सुधार, और मानव और भौतिक पूंजी में निवेश। पर ध्यान देने के साथ बहु-आयामी दृष्टिकोण का पालन करना पड़

सकता है। जबकि सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास के मुख्य चालक के रूप में जारी रहेगा, भारत को बड़े घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए अपने विनिर्माण आधार को व्यापक बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। क्षेत्रीय पुनर्व्यवस्था के अलावा, एक विकसित राष्ट्र के लिए भारत का मार्ग अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगा। यहां हम परिवर्तन की व्यापक रूपरेखा पर चर्चा करते हैं, पहले अर्थव्यवस्था-व्यापी स्तर पर और बाद में चुनिंदा लक्षित क्षेत्रों पर।

संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाना

विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय संस्थानों की गुणवत्ता और आर्थिक समृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध देखा गया है। डारोन एसेमोग्लू⁸ आर्थिक संस्थानों का वर्णन उन संस्थानों के रूप में करता है जो "खेल के आर्थिक नियम" निर्धारित करते हैं - विशेष रूप से, संपत्ति अधिकार प्रवर्तन की डिग्री, अनुबंधों का सेट जो लिखा और लागू किया जा सकता है, और नियम और विनियम जो एजेंटों को खुले आर्थिक अवसरों को निर्धारित करते हैं। इसके मूल में, कानून का शासन सार्वजनिक सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, न्याय तक पहुंच और जवाबदेही की गारंटी देता

⁸ <http://web.mit.edu/14.773/www/2003%20Class%20notes.pdf>

है। तकनीकी प्रगति से संस्थागत सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है, जैसा कि हालिया डिजिटलीकरण अभियान और उसके बाद सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता में वृद्धि से स्पष्ट है। संस्थागत गुणवत्ता सार्वजनिक क्षेत्र से आगे है; और ठोस कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों को बढ़ावा देने वाला एक संस्थागत ढांचा बनाने के प्रयास भी विश्वास, दीर्घकालिक स्थिरता और व्यावसायिक अखंडता का माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं (दास, 2023)।

वित्तीय व्यवस्था को गहरा बनाना

उत्पादक क्षेत्रों के लिए संसाधनों के आवंटन में सुधार के लिए घरेलू वित्तीय प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भारत में निवेश को मुख्य रूप से घरेलू बचत से बढ़ावा मिला है। जबकि भारत की बचत दर ईएमडीई की तुलना में अधिक है, इस बचत को उत्पादक संपत्तियों में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें नवाचार और प्रौद्योगिकी मदद कर सकती है। उधारकर्ताओं के ऋण विवरण की कमी और जानकारी की विषमता के साथ अच्छी संपार्श्विक की कमी, उधारदाताओं के लिए ऋण देने की चुनौती को बढ़ा देती है। वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों ने ऋण वितरण तंत्र में सुधार किया है, और बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों में और अधिक नवाचार और विभेदित बैंकिंग को आगे बढ़ाने की गुंजाइश तलाशने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और डेटा की उपलब्धता पर सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय क्रेडिट मूल्यांकन के लिए अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यापक आधार प्रदान करते हैं और इससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को ऋण देने में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को व्यापक बनाने की जरूरत है, अन्यथा वित्तीय पहुंच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर आ जाती है। इससे अर्थव्यवस्था के अप्रयुक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैंक संसाधन मुक्त हो जाएंगे। विभिन्न वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में नियामक आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करना, वैकल्पिक निवेश के अवसर विकसित करना, फिनटेक और डिजिटल नवाचार का उपयोग करना, निवेशक आधार को व्यापक बनाना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और विभिन्न

नीति निर्माताओं द्वारा नीतियों का समन्वित कार्यान्वयन वित्तीय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि

श्रम बल के कौशल-सेट में सुधार के साथ-साथ, अधिक कार्यशील आयु वाली आबादी को श्रम बल में लाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब तक, केवल पाँचवीं महिलाएँ ही श्रम शक्ति का हिस्सा हैं, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। कामकाजी महिलाओं के पक्ष में सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए जागरूकता प्रसारित कर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने; छात्रों और कर्मचारियों की विविधता बनाए रखने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित करना; सुविधाजनक काम के घंटे; कार्यस्थलों पर महिला-अनुकूल नीतियां और सुविधाएं, घर के नजदीक काम की उपलब्धता; और नौकरियों की बढ़ती औपचारिकता (पात्र, 2022) की आवश्यकता है।

ज्ञान-उन्मुख क्षेत्रों को लक्षित करना

जबकि निरंतर उच्च विकास के लिए एक व्यापक-आधारित दृष्टिकोण आवश्यक है, प्रमुख क्षेत्रों से लाभ उठाने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण जो विकास के सुलभ लाभों को प्रदान कर सकता है, उसे भी तलाशने की आवश्यकता है। सेवा क्षेत्र स्वयं को ऐसी रणनीति के लिए एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करता है। साहित्य सेवा क्षेत्र के विकास की दो अलग-अलग तरंगों की पहचान करता है। पहला "पारंपरिक" सेवाओं (जैसे व्यक्तिगत सेवाएं, खुदरा और थोक व्यापार, आदि) में विकास के प्रारंभिक चरण में अपेक्षाकृत कम आय स्तर पर होता है, जबकि दूसरा, संचार, कंप्यूटर और तकनीकी तथा व्यावसायिक सेवाएँ जो सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं और सीमा-पार व्यापार योग्यता के लिए अधिक गुंजाइश रखती हैं (इचेंग्रीन और गुप्ता, 2009) जैसे उद्योगों में उच्च आय पर होता है। भारत ने इस परिवर्तन की शुरुआत कर दी है; और इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) का निर्यात तेजी से राष्ट्रीय संपत्ति में योगदान दे रहा है। वैश्विक निगमों के लिए उपलब्ध भारतीय प्रतिभाओं के बड़े समूह और भारत में मौजूद 1500 वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में से 45 प्रतिशत को देखते हुए, जो नई प्रौद्योगिकियों में कुशल जनशक्ति तक पहुंच के साथ पर्याप्त मात्रा में हैं, भारत इस सफलता का

लाभ उठाने और अधिक कौशल-गहन और तेजी से डिजिटलीकृत सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ई-कॉमर्स, फिनटेक और एडटेक क्षेत्रों में तेजी से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की अगली लहर का नेतृत्व करने की उम्मीद है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल), बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्रों में अधिक विविध समाधानों के साथ, कंपनियां परिचालन के दृष्टिकोण से कुशल, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अत्यधिक उत्पादक होंगी।

नीतियों को पेशेवर सेवाओं (जैसे लेखांकन और कानूनी सेवाओं) के निर्यात को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें सेवाओं की आउटसोर्सिंग और भारतीय पेशेवरों के मौजूदा कौशल और विदेशी संगठनों से अपेक्षित आवश्यकताओं के बीच अंतर की पहचान शामिल हो सकती है। अंतराल को भरने और भारतीय फर्मों और पेशेवरों के बीच वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने के लिए विदेशी संस्थानों के साथ गठजोड़ पर विचार किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने की दिशा में पहल जारी रहनी चाहिए क्योंकि कुछ सेवाओं की भूमिका, जैसे कॉरपोरेट लेखांकन, व्यापारी बैंकिंग और कॉरपोरेट कानून, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), विलय और अधिग्रहण इत्यादि जैसी कॉरपोरेट गतिविधि में वृद्धि के साथ अधिक प्रमुखता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा, घरेलू फर्मों के पक्ष में बिग 4 अकाउंटिंग⁹/ बिग 3 प्रबंधन परामर्श¹⁰ फर्मों पर निर्भरता से हटकर घरेलू फर्मों की क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाने की नीतियां शुरू की जा सकती हैं।

एमएसएमई का संरचनात्मक परिवर्तन और भूमिका

कामकाजी उम्र वाली बड़ी आबादी के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए जनसांख्यिकीय लाभ पूरी तरह से तभी प्राप्त किया जा सकता है जब कृषि के बाहर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। आई और ईएमडीई की तुलना में, भारत में मूल्य वर्धित

और रोजगार में एमएसएमई की हिस्सेदारी कम है। मलेशिया, सिंगापुर, जर्मनी और जापान में सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान 40-50 प्रतिशत के बीच है जबकि रोजगार में उनकी हिस्सेदारी लगभग 70 प्रतिशत है। इसके विपरीत, भारत में, सकल मूल्य वर्धित और रोजगार में एमएसएमई की हिस्सेदारी क्रमशः 30 और 24 प्रतिशत कम है। इससे इस क्षेत्र का लाभ उठाने और मूल्य वर्धित तथा रोजगार दोनों में इसकी हिस्सेदारी बढ़ाने की संभावना है।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एमएसएमई के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से संगठित विनिर्माण क्षेत्र और एमएसएमई के बीच बेहतर तालमेल की उम्मीद है। कॉरपोरेट क्षेत्र को अत्यधिक अनुकूलित और विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक पार्कों का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इनोवेशन हब के रूप में कार्य करते हुए, ये औद्योगिक क्लस्टर घरेलू विनिर्माण को समर्थन देते हुए आपूर्ति शृंखला के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करेंगे। भौतिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, कार्यबल के कौशल को बढ़ाना और एमएसएमई को मूल्य शृंखला में एकीकृत करना विनिर्माण क्षेत्र के विकास में भारत की यात्रा को आकार देगा। इसके लिए भूमि उपलब्धता, श्रम बाजार सुदृढ़ता और त्वरित विवाद समाधान से संबंधित संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने की भी आवश्यकता होगी।

पर्यटन में संभावनाओं का दोहन

कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं सहित कई देशों के लिए, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र उनके सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान देता है। एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत को अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों, मजबूत वायु, जमीन और बंदरगाह संबंधित बुनियादी ढांचे और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता की समृद्ध क्षमता के रूप में एक बड़ा लाभ है। संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने, पर्यटक सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य और स्वच्छता और आईसीटी तत्परता में आगे के निवेश से इसका आकर्षण बढ़ेगा। नीति का ध्यान राज्य और नगरपालिका विभागों की डिजिटल तैयारी, आकांक्षी जिलों जैसे प्रतिस्पर्धी संघवाद और यात्रा और पर्यटन के लिए स्मार्ट सिटी कार्यक्रम, विशेष रूप से प्रमुख पर्यटन स्थलों और उसके आसपास

⁹ डेलॉइट, अन्स्ट एंड यंग (ईवाई), केपीएमजी, और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी)।

¹⁰ मैकिन्से एंड कंपनी, बेन एंड कंपनी और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप।

बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता बुनियादी ढांचे में सुधार को सुविधाजनक बनाने पर हो सकता है। पूर्वी एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के टेम्पलेट का उपयोग करके भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रवासी भारतीयों का लाभ उठाकर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिन्होंने प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्ती और संस्कृति के प्रदर्शन के साथ-साथ उदार यात्रा वातावरण का उपयोग किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा पर निरंतर जोर देकर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना

विकास बढ़ाने वाली रणनीति का पालन करते हुए, भारत को स्वच्छ ऊर्जा मार्ग को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति भी सचेत रहना होगा क्योंकि अंततः जलवायु संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करने से दीर्घकालिक विकास स्थिरता (आरबीआई, 2023) को खतरा हो सकता है। वर्तमान में, भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत में कोयले की हिस्सेदारी आधे से अधिक है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। पारंपरिक स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देते हुए, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न नीतिगत उपाय कर रही है। फिर भी, खपत और आर्थिक आकार में समग्र वृद्धि से निकट अवधि में ऊर्जा आयात की लागत में निरपेक्ष रूप से वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को एकत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं क्योंकि यह क्षेत्र पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक खनिज गहन है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (2021) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के साथ ऊर्जा के लिए भू-राजनीतिक जोखिम तेज हो जाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण कच्चे माल की बंदोबस्ती भौगोलिक रूप से अधिक केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कम ग्रीड कनेक्टिविटी और मौसम की स्थिति से जुड़ी अस्थिर आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा के लिए और अधिक जोखिम पैदा करती है।

इसे देखते हुए, उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की नियमित और स्थिर आपूर्ति बनाना आवश्यक है। इसलिए, भारत उन महत्वपूर्ण खनिजों का ऑडिट कर सकता है जो भारत के हरित परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं और इन क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दे सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों, रणनीतिक निवेशों का विस्तार कर सकता है और आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता ला सकता है।

आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना

वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों का प्रभाव तेजी से घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं तक फैलता है, खासकर उन देशों से जहां से भारत कच्चे माल और मध्यवर्ती की अपनी आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है (पात्र एवं अन्य, 2022)। इस प्रकार, भारत के लिए अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करने की दिशा में काम करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा, महामारी और बढ़े हुए भू-राजनीतिक तनाव-प्रेरित आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के अनुभव ने आपूर्ति शृंखला के लचीलेपन और सुदृढ़ता को बनाए रखने या समग्र आघातों के अनुकूल होने की क्षमता में रुचि पैदा की है।

लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने से महत्वपूर्ण लाभ होंगे - लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने से ₹10 लाख करोड़ तक की बचत हो सकती है और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है (नीति आयोग, 2021)¹¹। उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) को सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था: (i) यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) के माध्यम से दक्षता और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में सुधार की नीतियों के माध्यम से 2030 तक वैश्विक स्तर के बराबर लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना।) पीएम गति शक्ति के तहत; और (ii) एआई और एमएल के उपयोग के साथ एक कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा-संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना।

¹¹ <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-06/FreightReportNationalLevel.pdf>

हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि लॉजिस्टिक्स लागत का एक बड़ा हिस्सा परिवहन (कुल लॉजिस्टिक्स लागत का 62 प्रतिशत) से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए परिवहन लागत को कम करने के लिए सड़क परिवहन पर निर्भरता को 25 से 30 प्रतिशत तक कम करना होगा। साथ ही, रेलवे के माध्यम से माल परिवहन को मौजूदा 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत¹² करने की भी आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए, फर्मों/इकाइयों को लागत कम करके और अलग रेलवे माल दुलाई पथ बनाकर रेलवे माल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

VI. निष्कर्ष

अगले 25 वर्षों तक 7.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकता है। इस लेख में प्रस्तुत विश्लेषण से पता चलता है कि यह संभव है, जो अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक सुधारों, निवेश, लॉजिस्टिक्स और डिजिटलीकरण पर नीति केन्द्रित विकास बढ़ाने वाले प्रभाव, अनुकूल जनसांख्यिकी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए श्रम बल को बढ़ाने और विनिर्माण, निर्यात, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल करते हुए क्षेत्रीय नीति पहलों से प्रेरित है।

हालाँकि, पूंजी भंडार, बुनियादी ढाँचे और लोगों के कौशल सेट के मौजूदा स्तर को देखते हुए यह कार्य आसान नहीं हो सकता है। भारत को श्रम शक्ति के बड़े समूह को उत्पादक रूप से संलग्न करने और ज्ञान-उन्मुख क्षेत्रों में विकास के अवसरों का दोहन करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जबकि अकुशल/अर्ध-कुशल श्रम बल को एमएसएमई में समाहित किया जा सकता है, नए युग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए युवा पीढ़ी को कौशल बढ़ाने और तैयार करने की आवश्यकता होगी। जबकि पूंजी में वृद्धि और मानव संसाधनों को सशक्त बनाना भारत को वांछित विकास पथ पर ले जा सकता है, इस परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

संदर्भ

Aghion, P. and Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. *Econometrica*, 60, 323–51.

Bulman, D., Eden, M. and Nguyen, H. (2014). Transitioning from Low-Income Growth to High-Income Growth – Is There a Middle-Income Trap? World Bank Policy Research Working Paper No. 7104.

Das, S. (2023). Governance in Banks: Driving Sustainable Growth and Stability. Inaugural Address at the Conference of Directors of Banks organised by the Reserve Bank of India for Public Sector Banks on May 22, 2023 in New Delhi and Private Sector Banks on May 29, 2023 in Mumbai.

Eichengreen, B. and Gupta, P. (2009). The Two Waves of Service Sector Growth. NBER Working Paper Series. No. 14968. Cambridge, MA: NBER.

Eichengreen, B., Park, D. and Shin, K. (2012). When Fast-Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China. *Asian Economic Papers* 11 (1): 42–87.

International Energy Agency (2021). *World Energy Outlook 2021*. Paris.

Kim, J. and Park, J. (2017). The Role of Total Factor Productivity Growth in Middle Income Countries. ADB Economics Working Paper Series No. 527, November.

Krishna, K.L., Goldar, B., Das, D.K., Aggarwal, S.C., Erumban, A.A. and Das, P.C. (2022). *India Productivity Report*. Centre for Development Economics, University of Delhi.

Patra, M.D. (2022). India@75. Speech delivered at Bhubaneswar in an event to celebrate Azadi Ka Amrit Mohotsav organised by Reserve Bank of India - August 13.

Patra, M.D., Behera, H. and Gajbhiye, D. (2022). Measuring Supply Chain Pressures on India. *RBI Bulletin*, April.

¹² <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883514>

Reserve Bank of India (2023). *Report on Currency and Finance 2022-23*. Mumbai.

Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-run Growth. *Journal of Political Economy*, 94, 1002–37.

Romer, P.M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy* 98, S71–S102.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312-320.

Swan, T. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Record*, 32 (63), 334-361

Tran, V. T. (2013). The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of Southeast Asian Nations. ADBI Working Paper No. 421.